

सरकारी वित्त 2021-22: एक अर्ध-वार्षिक समीक्षा*

सरकारी वित्त ने दूसरी लहर के लिए उल्लेखनीय आघात सहनीयता प्रदर्शित किया, जिसमें यह कर संग्रह अपेक्षाओं को पार कर गया, और सरकारी व्यय मोटे तौर पर उच्च महामारी संबंधी खर्च के बावजूद बजट अनुमानों के अनुरूप बना रहा। केंद्र और राज्यों दोनों के लिए व्यय की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो एक टिकाऊ विकास सुधार के लिए अच्छा है। आगे बढ़ते हुए, सामान्य सरकारी राजकोषीय घाटा, जो 2021-22 की पहली छमाही में कम रहा, चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में विकास में सुधार को समर्थन और बनाए रखने के लिए व्यय में तेजी लाने की अनुमति देता है।

I. परिचय

वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट एक ऐसे मोड़ पर पेश किया गया था जब अर्थव्यवस्था महामारी की पहली लहर के बाद आई भीषण मंदी से एक मजबूत प्रोत्साहन-नेतृत्व वाला सुधार देख रही थी, लेकिन दूसरी लहर की संभावना के बारे में अनिश्चितता के बीच। तदनुसार, बजट में एक नाजुक संतुलन का अनुसरण किया गया, एक चुनौतीपूर्ण व्यापक आर्थिक वातावरण में राजकोषीय समेकन की व्यवहार्य डिग्री का लक्ष्य रखते हुए एक व्यापक-आधार वाले और टिकाऊ आर्थिक सुधार के लिए समर्थन बनाए रखा। बजट में सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को 2020-21 (आरई) में सकल घरेलू उत्पाद के 9.5 प्रतिशत से 2021-22 (बीई) में 6.8 प्रतिशत करने की परिकल्पना की गई है।¹ राज्यों ने अपने जीएफडी में 2020-21 (आरई) में सकल घरेलू

उत्पाद के 4.7 प्रतिशत से 2021-22 (बीई) में 3.7 प्रतिशत तक समेकन का बजट रखा। दूसरी लहर, बाद में अप्रैल-मई 2021 के दौरान मानव जीवन के नुकसान के मामले में अधिक गंभीर हो गई, लेकिन आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव स्थानीय प्रतिबंधों और वायरस के साथ रहने के लिए बेहतर अनुकूलन के माध्यम से निहित था। सरकारी वित्त ने उल्लेखनीय लचीलापन और उछाल दिखाया, और इसके परिणामस्वरूप, दूसरी लहर द्वारा लगाए गए अतिरिक्त व्यय बोझ के बावजूद, सरकारी खर्च मोटे तौर पर बजट अनुमानों के अनुरूप रहा है। पूंजीगत व्यय पर सरकार के जोर के परिणामस्वरूप व्यय की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ - मध्यम अवधि में विकास समर्थक राजकोषीय समेकन के लिए एक आवश्यक शर्त। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में सभी प्रमुख कर शीर्षों में मजबूत वृद्धि दर्ज करने के साथ, केंद्र का कर संग्रह, प्राप्तियों के संबंध में अपेक्षाओं को पार कर गया। राज्यों के कर संग्रह ने भी मजबूत वृद्धि का प्रदर्शन किया, हालांकि केंद्र के समान गति से नहीं, और वह 2021-22 की पहली छमाही में अपने पूर्व-महामारी के स्तर पर पहुंच गए हैं।

शेष लेख को इस प्रकार संरचित किया गया है: खंड II 2021-22 की पहली छमाही के लिए केंद्र और राज्यों (तिमाही आवृत्ति पर) के लिए प्राप्ति और व्यय परिणामों का विश्लेषण करता है। खंड III प्रमुख घाटे के संकेतकों और उनके वित्तपोषण के संदर्भ में परिणामों से संबंधित है। खंड IV 2021-22 की दूसरी छमाही के अनुमानों के साथ ति.1 और ति.2: 2021-22 के लिए सामान्य सरकारी वित्त पर अनुमान प्रस्तुत करता है। खंड V समापन टिप्पणियों और निकट अवधि के वित्तीय दृष्टिकोण को निर्धारित करता है।

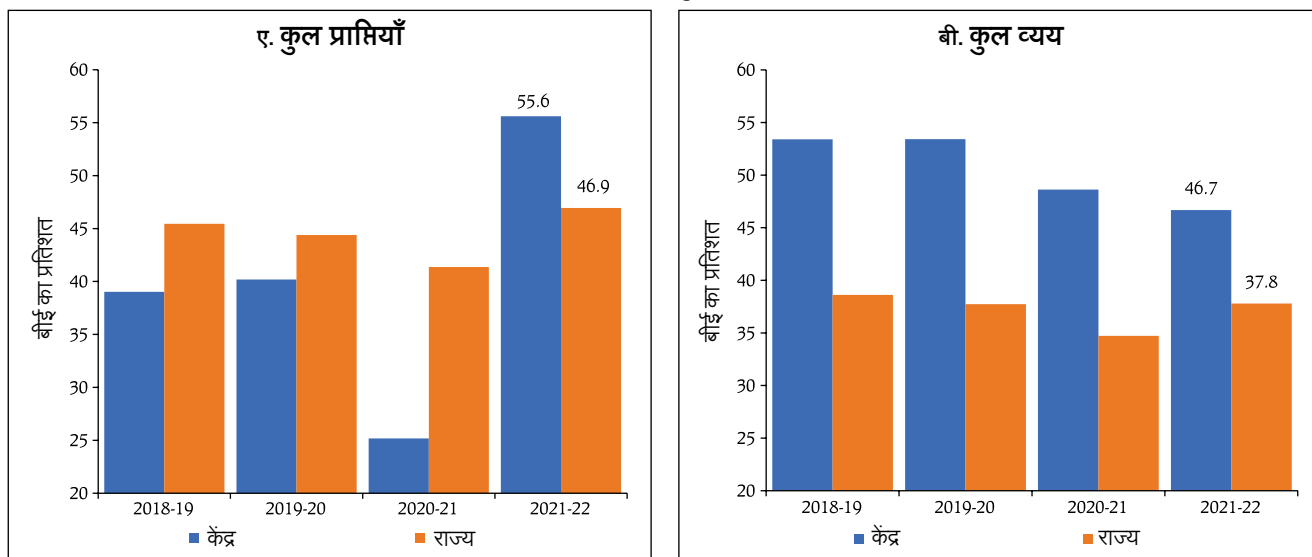
II. वर्ष 2021-22 ति. 1 और ति. 2 में राजकोषीय परिणाम:

केंद्र सरकार की कुल प्राप्तियों ने अपने प्रवृत्ति स्तर पर एक उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया और कुल व्यय 2021-22 की पहली छमाही में निहित रहा, दूसरी लहर द्वारा आवश्यक अतिरिक्त व्यय के बावजूद, क्योंकि सरकार ने परिहार्य व्यय को कम करने के लिए एहतियाती उपाय किए। राज्य का वित्त भी 2021-22 की पहली छमाही में अपने पूर्व-महामारी स्तर पर वापस आ गया।

* यह लेख आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के रचित सोलंकी, सक्षम सूद, इप्सिता पाद्री, डॉ. सोमनाथ शर्मा, डॉ. समीर रंजन बेहरा और डॉ. अत्री मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया है। टीम, डॉ. देब प्रसाद रथ को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देती है। लेखक श्री सितिकंठ पटनायक और श्री बिचित्रानंद सेठ की टिप्पणियों और बहुमूल्य सुझावों के लिए भी उनके प्रति आभारी हैं। व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को व्यक्त करें।

¹ ये अनुमान 14.4 प्रतिशत की मामूली जीडीपी वृद्धि और 1.2 की कर उछाल और राजस्व व्यय में मामूली संकुचन की सामान्य धारणाओं पर आधारित थे।

चार्ट 1: पहली छमाही में कुल प्राप्तियाँ और व्यय



स्रोत: लेखा महा नियंत्रक (सीजीए): और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी)

राज्यों ने अपनी बजटीय प्राप्तियों का 46.9 प्रतिशत संग्रह किया जो पिछले तीन वर्षों के तदनुरूपी आंकड़ों से अधिक है। व्यय पक्ष पर, 2021-22 की पहली छमाही में व्यय बजट लक्ष्य का 37.8 प्रतिशत था, जो व्यापक रूप से पूर्व-महामारी के वर्षों (चार्ट 1) के दौरान औसत के अनुरूप था।

ए. प्राप्तियाँ

केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों ने ति.1: 2021-22³ में एक मजबूत वृद्धि दर्ज की, क्योंकि दूसरी लहर के बावजूद कर राजस्व में उच्च उछाल दर्ज किया गया और गैर-कर राजस्व को रिजर्व बैंक से बजटीय लाभांश हस्तांतरण से अधिक से बढ़ावा मिला। दूसरी तिमाही में राजस्व प्राप्तियों में 35.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, इसने एच1 में समग्र रूप से बीई का 60.4 प्रतिशत का उच्च स्तर देखा। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ⁴ में भी एच1:2021-22 की

तुलना में एच1:2020-21 में सुधार हुआ, लेकिन 2019-20 के स्तर से कम हो गया (चार्ट 2 ए और बी)।

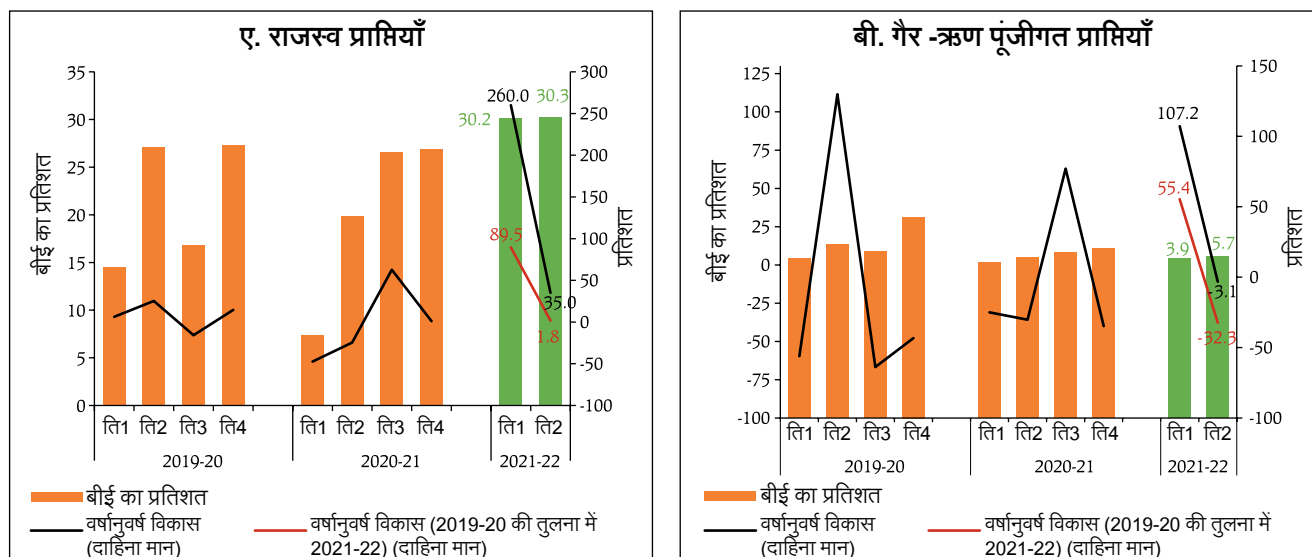
राज्यों की राजस्व प्राप्तियाँ भी महामारी की दूसरी लहर के लिए लचीला बनी हुई हैं, कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में ति.1: 2021-22 में 33.7 प्रतिशत की सालाना वृद्धि और 2019-20 की इसी तिमाही में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में भी इसी तरह का प्रदर्शन कायम रहा, जिसमें साल-दर-साल राजस्व में 21.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, 2021-22 की पहली छमाही में राज्यों की राजस्व प्राप्तियाँ 2020-21 की पहली छमाही में (2019-20 की पहली छमाही में से 8.2 प्रतिशत) की तुलना में 26.7 प्रतिशत अधिक थीं। राज्यों की गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों ने भी 2021-22 की पहली और दूसरी तिमाही दोनों में उच्च वृद्धि दर्ज की, हालांकि काफी उतार-चढ़ाव के साथ (चार्ट 3)।

² 26 राज्यों के लिए समग्र आंकड़ों के आधार पर, जिसके लिए 2021-22 की दूसरी तिमाही तक का पूरा ऐतिहासिक और अद्यतन डेटा उपलब्ध है।

³ 2020-21 की तुलना में 260.0 प्रतिशत और 2019-20 की तुलना में 89.5 प्रतिशत की वृद्धि।

⁴ गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में ऋण और अग्रिम की वसूली और विविध पूंजी प्राप्तियाँ (विनिवेश और अन्य प्राप्तियाँ) शामिल हैं।

चार्ट 2: केंद्र की प्राप्ति का तिमाहीवार विवरण



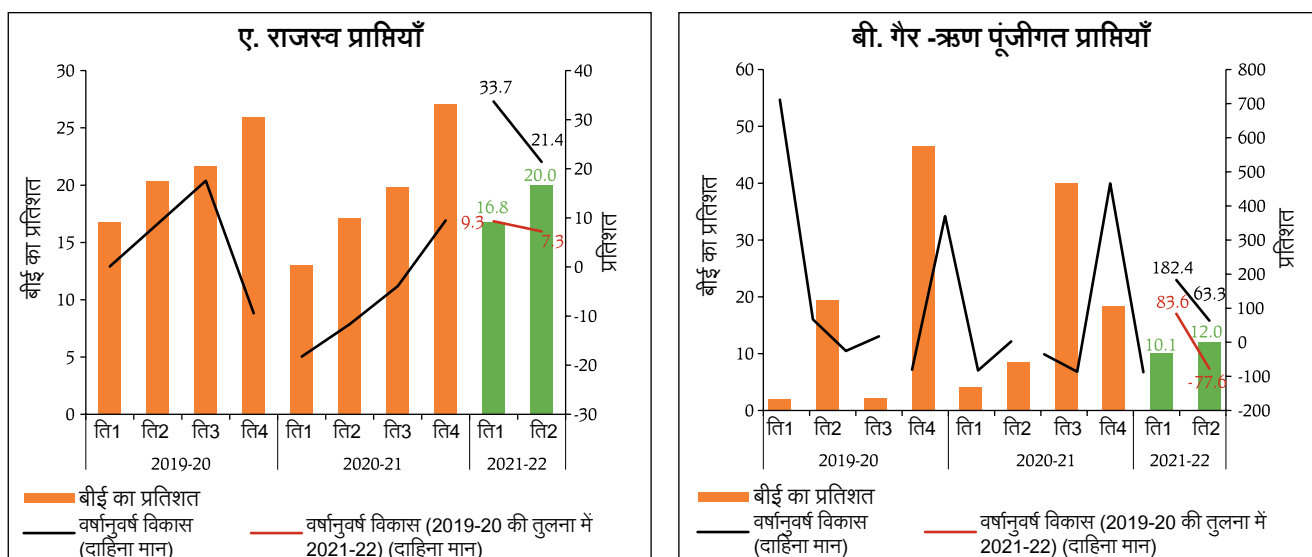
स्रोत: सीजीए

केंद्र के प्रत्यक्ष कर संग्रह ने 2021-22 की पहली छमाही में 83.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जिसका नेतृत्व आयकर और निगम कर में क्रमशः ⁵ 64.7 प्रतिशत और 105.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ किया गया, जो मजबूत कॉर्पोरेट प्रदर्शन के आधार पर था। राज्यों के लिए, स्टॉप शुल्क जो स्वयं के प्रत्यक्ष कर

राजस्व का 85 प्रतिशत से अधिक है, ति.1: 2021-22 में दोगुने से अधिक हो गया है; ति.2 में 53.4 प्रतिशत (चार्ट 4) की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।

व्यापार गतिविधि में सुधार और उच्च आयात मांग के कारण सीमा शुल्क संग्रह में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के कारण

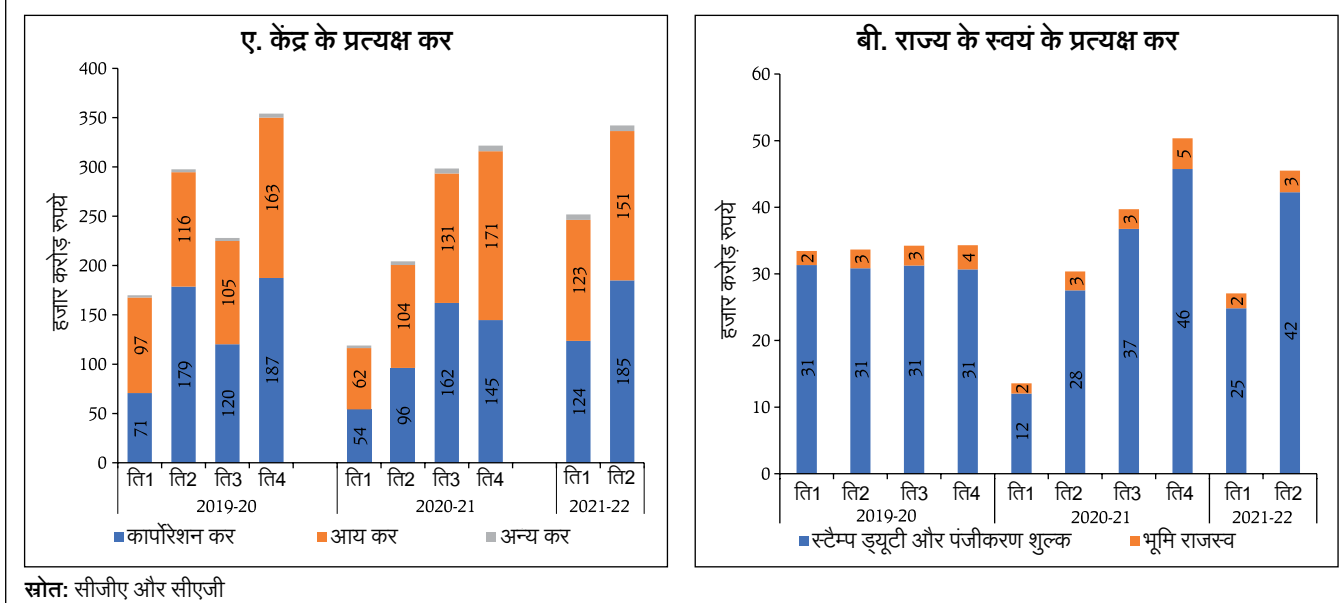
चार्ट 3: केंद्र की प्राप्ति का तिमाहीवार विवरण



स्रोत: सीजीए

⁵ 2019-20 में, आय और निगम करों में क्रमशः 28.7 प्रतिशत और 23.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चार्ट 4: तिमाही प्रत्यक्ष कर संग्रहण



पहली छमाही के दौरान केंद्र के अप्रत्यक्ष कर संग्रह में भी वृद्धि हुई। महामारी प्रेरित आपातकाल उपाय के रूप में अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए पिछले साल (मार्च और मई 2020) में लगाए गए उच्च शुल्क के कारण इस अवधि के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रह में 2020-21 (2019-20 की तुलना में 79.0 प्रतिशत) की तुलना में 33.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

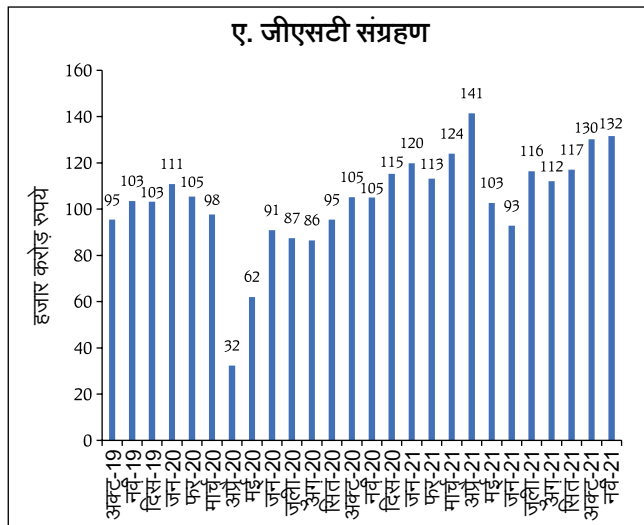
जीएसटी संग्रह (केंद्र के साथ राज्य) पहली छमाही में क्रमशः 2020-21 और 2019-20 के स्तर पर 50.1 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। महामारी से संबंधित प्रतिबंधों के कारण मई-जून में जीएसटी राजस्व में गिरावट आई थी, लेकिन इसके बाद आर्थिक सुधार के अनुरूप और कर प्रशासन द्वारा कर चोरी को रोकने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के कारण जल्दी से ठीक हो गया। नवंबर 2021 में, जीएसटी संग्रह ने 25.3 प्रतिशत⁶ की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज करके ₹1.32 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो जीएसटी की शुरुआत के बाद से दूसरा सबसे अधिक है। अप्रैल-अक्टूबर के दौरान 1 लाख करोड़ रुपये के बजटीय जीएसटी मुआवजा उपकर संग्रह का लगभग पाँच में से तीसरा हिस्सा वसूल किया

गया। केंद्र सरकार ने जीएसटी मुआवजा उपकर के बदले बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत 2021-22 में राज्यों को जारी की जाने वाली ₹1.59 लाख करोड़ की पूरी राशि भी हस्तांतरित कर दी है। राज्यों को अपने खर्च की प्रभावी ढंग से योजना बनाने में सक्षम बनाने के लिए फ्रंट-लोडिंग की गई है। राज्यों के जीएसटी संग्रह में वर्ष-दर-वर्ष पहली तिमाही में 71.6 प्रतिशत और वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में 27.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें गुजरात, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे कई राज्यों ने वर्ष 2020-21 की पहली छमाही की तुलना में वर्ष 2021-22 की पहली छमाही 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की (चार्ट 5)। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर मोर्चे पर बेहतर राजस्व स्थिति को देखते हुए, केंद्र ने नवंबर में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि जो महामारी की पहली लहर के दौरान पेश की गई थी, को आंशिक रूप से वापस ले लिया। राज्यों ने भी इसका अनुसरण करते हुए ईंधन पर अपनी वैट दरों को कम किया (बॉक्स 1)।

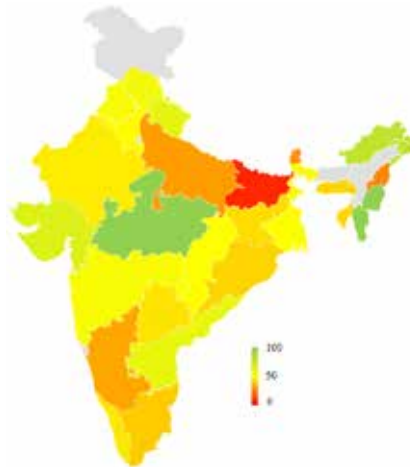
केंद्र के गैर-कर राजस्व में भी 2021-22 की पहली छमाही के दौरान रिजर्व बैंक से बजटीय अधिशेष हस्तांतरण से अधिक

⁶ 2019-20 की तुलना में 27.1 प्रतिशत की वृद्धि

चार्ट 5: जीएसटी निष्पादन



बी. वर्ष 2021-22 की पहली छमाही राज्य-वार व-द-व विकास दर



नोट: राज्य-वार जीएसटी के आंकड़े का संबंध राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए जाने वाले आंकड़ों से है
स्रोत: सीजीए; ई -राज्य संबंधी आंकड़े; और सीबीआईसी

होने के कारण वृद्धि हुई (चार्ट 6)। विनिवेश के मोर्चे पर, 1.75 लाख करोड़ रुपये के बजटीय विनिवेश लक्ष्य का केवल 5.2

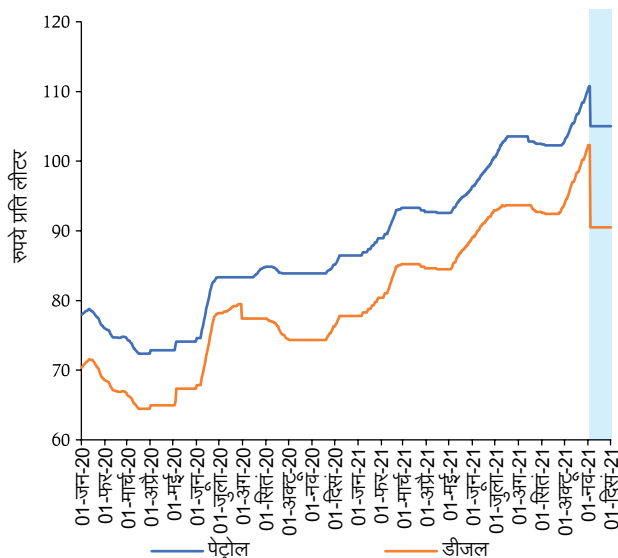
प्रतिशत ही पहली छमाही में जुटाया गया है। हालांकि, एयर इंडिया की प्रस्तावित बिक्री की प्रगति ने सरकार के विनिवेश कार्यक्रम को

बॉक्स 1: ईंधन करों में कमी का राजस्व प्रभाव

अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों (चार्ट 1.1) के महत्वपूर्ण रूप से बढ़ने के परिणामस्वरूप पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी से वृद्धि से उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए, केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क को 4 नवंबर, 2021 से क्रमशः ₹5 और ₹10 प्रति लीटर कम करने का फैसला किया। केंद्र के बाद, कई राज्यों ने भी अपने मूल्य वर्धित कर (वैट) को पेट्रोल में ₹0.8 से ₹10.0 प्रति लीटर और डीजल में ₹1.4 से ₹7.0 प्रति लीटर की सीमा में घटा दिया।

पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर (वैट) / बिक्री कर में कमी से प्रत्यक्ष अल्पकालिक राजस्व हानि होती है, लेकिन बाद में खपत और निवेश की मांग की अपेक्षित वृद्धि के कारण आय प्रभाव के माध्यम से राजस्व में कुछ वृद्धि की गुंजाइश होती है। मध्यम अवधि में, ईंधन की कीमतों में कमी से लागत के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है और इससे व्यापार और उपभोक्ता भावना में सुधार हो सकता है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में हालिया कटौती के संभावित वित्तीय प्रभाव (चार्ट 1.2 ए) और बाद में 23 राज्यों द्वारा वैट / बिक्री कर में कमी (चार्ट 1.2 बी) का विश्लेषण यहां किया गया है।

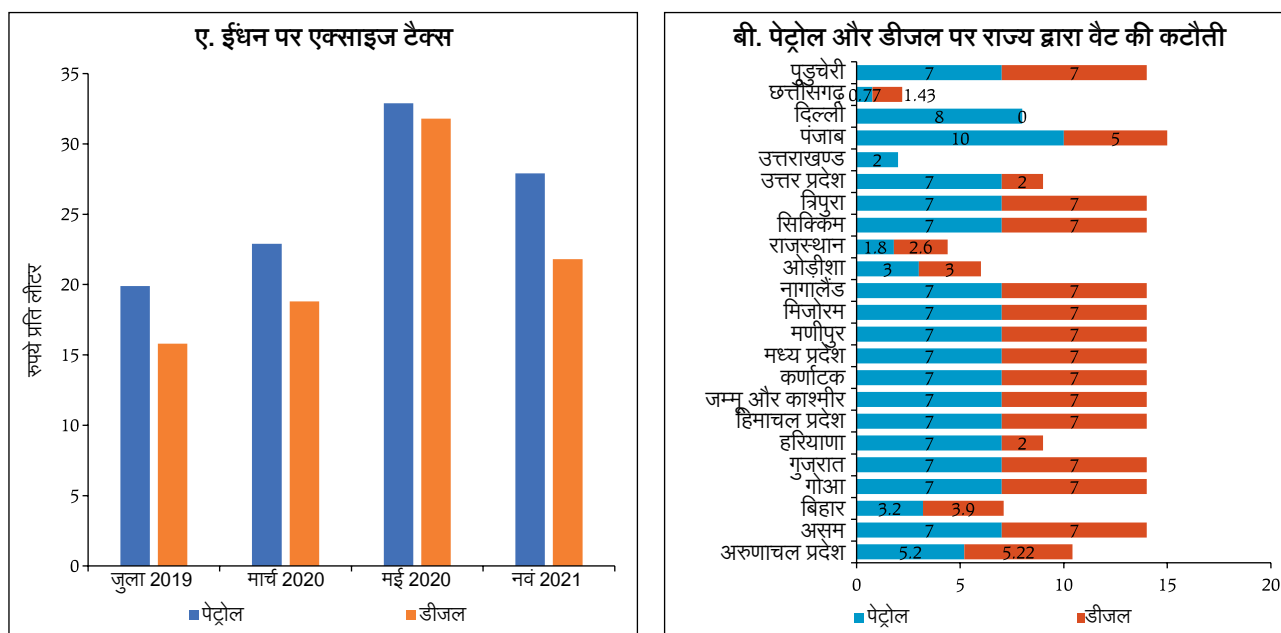
चार्ट 1.1: पेट्रोल और डीजल खुदरा मूल्य



एक्साइज और वैट/ सेल्स टैक्स में कमी किए जाने के बाद की अवधि शेडेड एरिया है
टिप्पणी: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में खुदरा मूल्य का औसत
स्रोत: पीपीएसी

(Contd...)

चार्ट 1.2: ईंधन पर एक्साइज और वैट में कमी



स्रोत: सीजीए; ई-राज्य के आंकड़े; और सीबीआईसी

केंद्र को राजस्व हानि का अनुमान नवंबर-मार्च के दौरान पेट्रोल और डीजल की अखिल भारतीय अनुमानित खपत को उत्पाद शुल्क में इसी कटौती के साथ गुणा करके लगाया जाता है। पेट्रोल और डीजल की राज्य-वार खपत का अनुमान (नवंबर-मार्च 2021-22) ⁷ पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी) से पेट्रोल और डीजल के राज्य-वार बिक्री डेटा का उपयोग कर रहा है। राज्य-वार राजस्व हानियों की गणना कीमत में

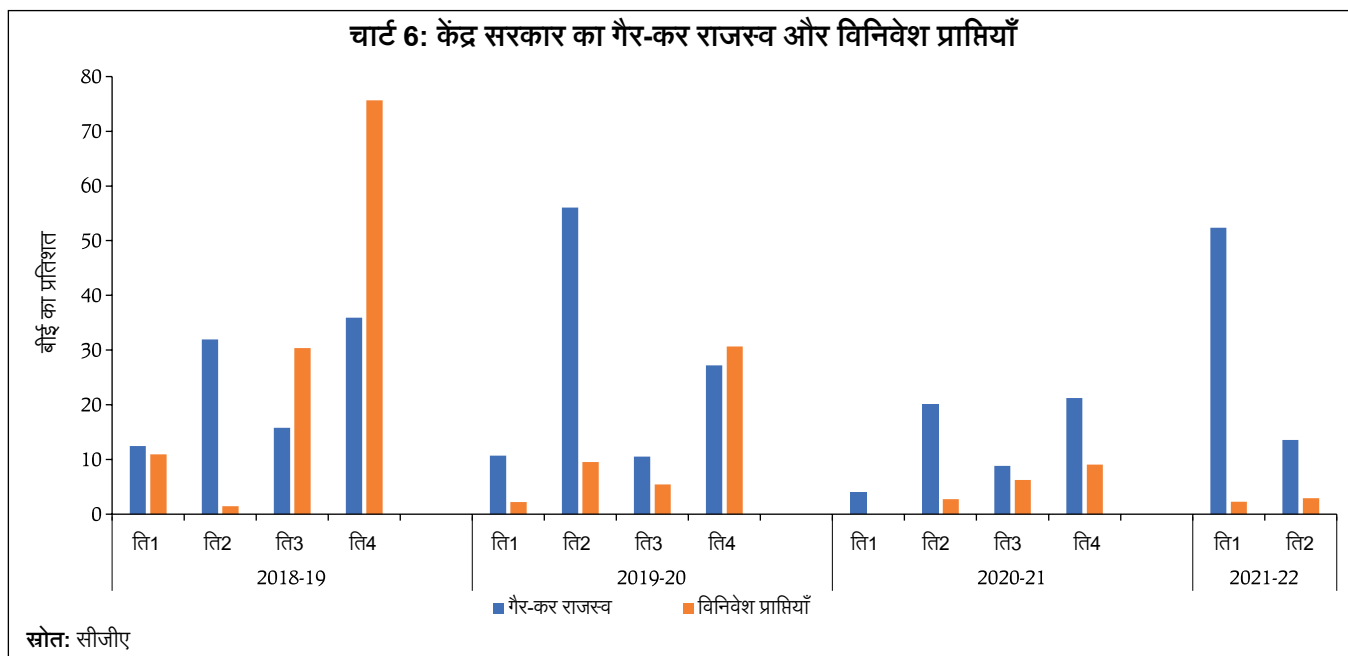
राज्य-विशिष्ट कमी (वैट/बिक्री कर में कमी के कारण) के साथ इन मात्राओं को गुणा करके की जाती है।

2021-22 में केंद्र को राजस्व हानि सकल घरेलू उत्पाद का 0.2 प्रतिशत होने का अनुमान है जबकि वैट / बिक्री कर में कटौती के कारण राज्यों को राजस्व हानि सकल घरेलू उत्पाद का 0.1 प्रतिशत होने का अनुमान है।

गति प्रदान की है। केंद्र का लक्ष्य परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से संसाधन जुटाना भी है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत, 2021-22 से 2024-25 तक, चार साल की अवधि में, ₹ 6.0 लाख करोड़ की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान है, वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित ₹0.88 लाख करोड़ के सांकेतिक मूल्य के साथ। हालांकि, वास्तविक प्राप्ति समय, लेनदेन संरचना

और निवेशक की रुचि पर निर्भर करेगी। राज्यों के लिए, गैर-कर राजस्व में क्रमशः 2021-22 की पहली और दूसरी तिमाही में 40.2 प्रतिशत और 53.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (वर्ष 2019-20 की पहली और दूसरी तिमाही की तुलना में क्रमशः 15.9 प्रतिशत और 20.6 प्रतिशत क्रमशः)।

⁷ फुटनोट: दिल्ली और छत्तीसगढ़ के लिए, यह दिसंबर से मार्च 2021-22 तक है।

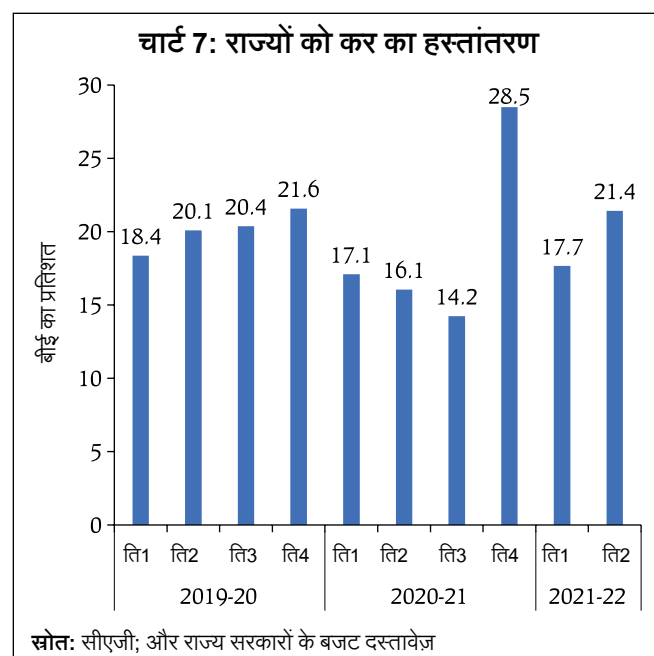


राज्यों को कर अंतरण में 2021-22 की पहली तिमाही के लिए लगभग 12 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। हालांकि, राज्यों के बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में, हस्तांतरण मोटे तौर पर 2020-21 और 2019-20 में उन लोगों के अनुरूप थे। वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के लिए, स्थानांतरण पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.3 प्रतिशत अधिक थे और राज्यों के बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में वे पिछले दो वर्षों (चार्ट 7) की ति2 की तुलना में भी अधिक थे।

बी. व्यय

केंद्र ने दूसरी लहर के जवाब में जून 2021 में 6.3 लाख करोड़ रुपये के राजकोषीय पैकेज की घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत खाद्यान्नों के मुफ्त प्रावधानों को नवंबर तक बढ़ाना, उर्वरकों के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव के कारण आवश्यक बढ़ी हुई उर्वरक सब्सिडी, सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के उपाय शामिल हैं। और कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजनाएं। जबकि इनमें से कुछ उपायों ने बजट राशि के अलावा और उससे अधिक अतिरिक्त व्यय का नेतृत्व किया, एक बड़ा हिस्सा चलनिधि समर्थन के रूप

में था और इसमें कोई अतिरिक्त राजकोषीय बोझ नहीं था। इसके बाद, जुलाई 2021 में शुरू की गई अनुदान की पहली अनुपूरक मांग में अतिरिक्त व्यय उपायों का प्रस्ताव किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 23,675 करोड़ रुपये का शुद्ध नकद व्यय हुआ। सरकार ने ति2: 2021-22 में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों पर व्यय प्रतिबंधों के माध्यम से खर्च को सीमित करने के

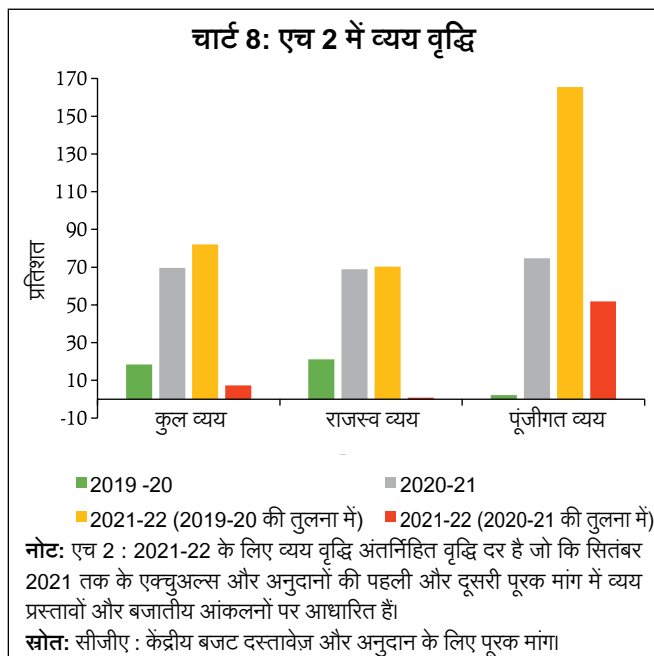


⁸ इसे मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है (परिशिष्ट तालिका 5)।

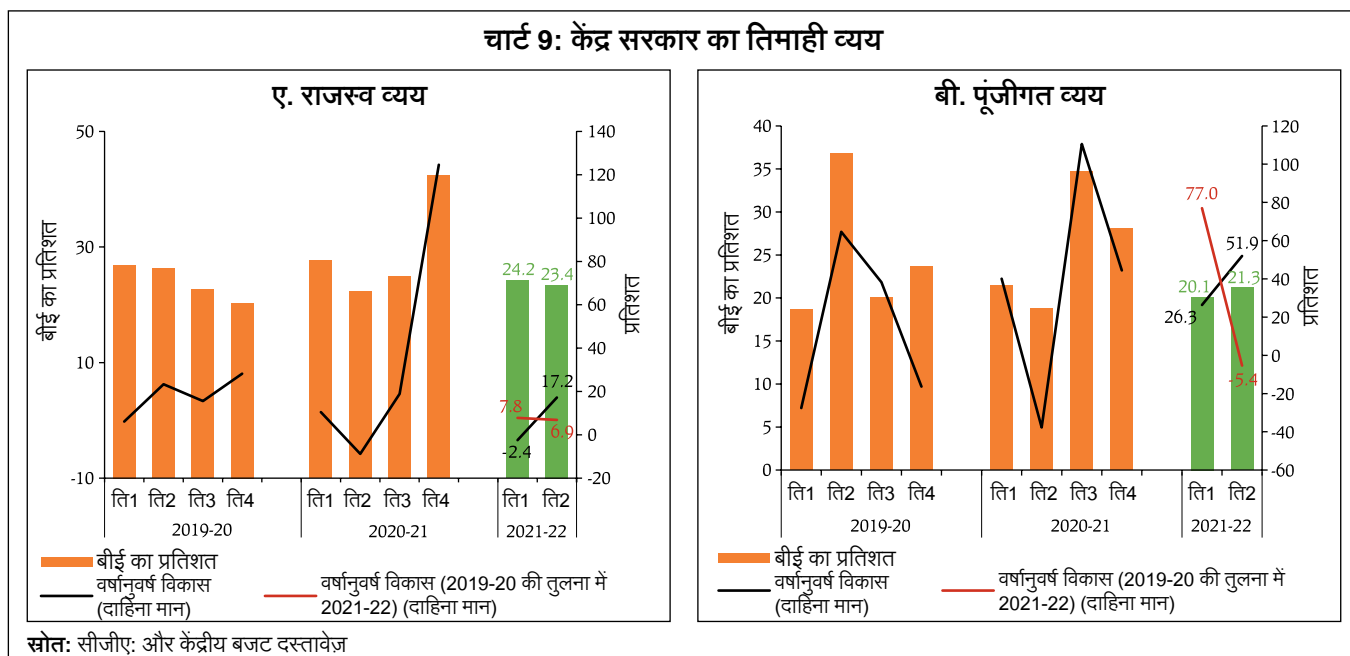
लिए एहतियाती कदम उठाए (इन व्यय सीमाओं को 24 सितंबर, 2021 से शिथिल कर दिया गया है)। नतीजतन, महामारी से संबंधित विस्तारवादी उपायों के बावजूद, कुल व्यय एच 1: 2021-22 के दौरान बीई के 46.7 प्रतिशत पर सीमित रहा, जबकि 2020-21 और 2019-20 की पहली छमाही के दौरान क्रमशः 48.6 प्रतिशत और 53.4 प्रतिशत था।

आगे बढ़ते हुए, 2021-22 की दूसरी छमाही में एक व्यय बढ़ोत्तरी की उम्मीद है, अनुदान के लिए पूरक मांग के दूसरे बैच के संबंध में, जिसने ₹ 2.99 लाख करोड़ के शुद्ध नकद व्यय का प्रस्ताव किया है - राजस्व व्यय पर ₹ 2.33 लाख करोड़ और ₹ 0.66 पूंजीगत व्यय पर लाख करोड़। अनुदान की पहली और दूसरी अनुपूरक मांग में बजट अनुमानों की तुलना में ₹3.23 लाख करोड़ की वृद्धि होती है, जो 2020-21 की दूसरी छमाही की तुलना में कुल व्यय में 2021-22 की दूसरी छमाही में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि और 2019-20 की दूसरी छमाही की तुलना में 82.0 प्रतिशत की वृद्धि में तब्दील हो जाती है (चार्ट 8)।

दूसरी तिमाही में उच्च राजस्व व्यय के कारण पहली छमाही में कुल मिलाकर 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में ति.1: 2021-22 में राजस्व व्यय में 2.4 प्रतिशत की कमी आई थी (हालांकि ति.1: 2019-20 की तुलना में 7.8 प्रतिशत अधिक), आंशिक रूप से ति.1: 2020-21 में उच्च आधार के



कारण जब व्यय करना पड़ा और महामारी की पहली लहर से निपटने के लिए उसे बढ़ाना भी पड़ा। व्यय का लक्ष्य रणनीतिक रूप से पूंजीगत व्यय की ओर झुका हुआ था, जो 2020-21 की पहली छमाही में 38.3 प्रतिशत की वर्ष -दर -वर्ष वृद्धि के साथ था (2019-20 की तुलना में 22.3 प्रतिशत की वृद्धि) (चार्ट 9 ए और बी)।



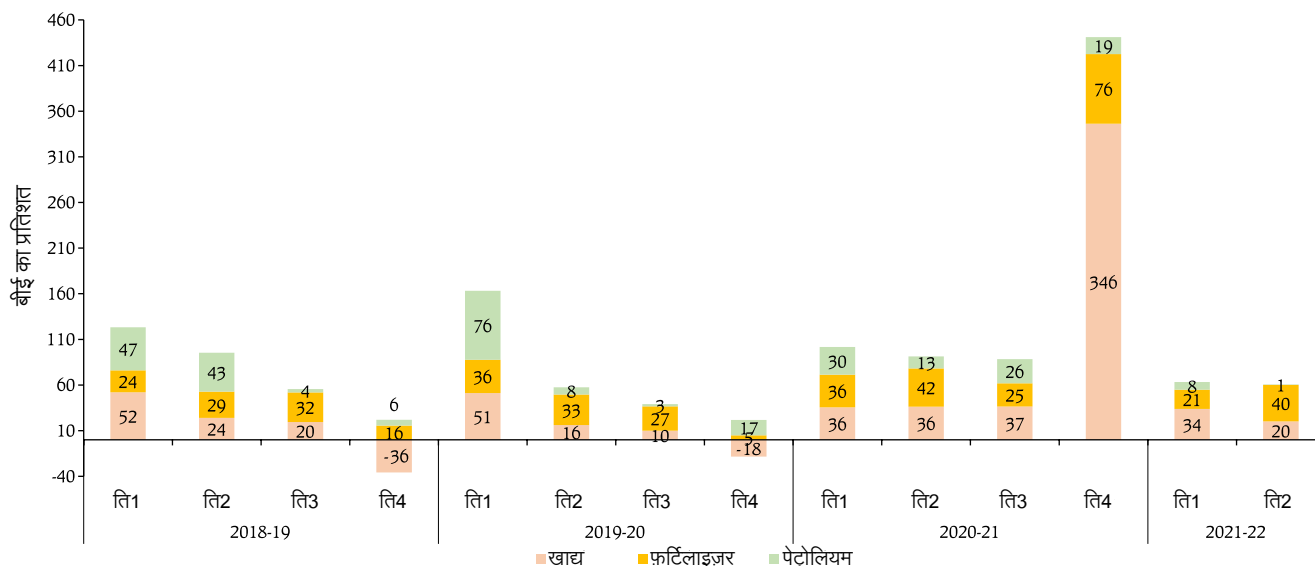
प्रधान मंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के आरंभ होने से भी देश में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के आधार पर, गति शक्ति प्लेटफॉर्म सभी मौजूदा और प्रस्तावित आर्थिक क्षेत्रों को उनके मल्टी-मोडल इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेज (रेल, सड़क आदि) के साथ मैप करेगा। विभिन्न मंत्रालयों की अलग-अलग परियोजनाओं के अनुमोदन को गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूपता के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, इस प्रकार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक समग्र और समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा। राज्यों द्वारा पूंजीगत संपत्ति निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र ने नई या जारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की एक योजना शुरू की है।

केंद्र सरकार की प्रमुख सब्सिडी, जिसमें भोजन, ईंधन और उर्वरक शामिल हैं, पिछले वर्ष की इसी अवधि में बीई के 68.6 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 की पहली छमाही में बीई का

53.8 प्रतिशत था। प्रमुख सब्सिडियों पर कुल व्यय का 72.5 प्रतिशत खाद्य सब्सिडी था (चार्ट 10)।

राज्यों के राजस्व व्यय में वर्ष 2021-22 की पहली और दूसरी तिमाही में क्रमशः 10.9 प्रतिशत और 14.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (वर्ष 2019-20 की इन्हीं तिमाहियों की तुलना में क्रमशः 26.0 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत)। राज्यों के बजट अनुमानों के प्रतिशत के अनुसार, एच1:2021-22 में राजस्व व्यय मोटे तौर पर पिछले वर्ष के पैटर्न के अनुरूप है। पूंजीगत व्यय के मोर्चे पर, केंद्र द्वारा 'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता' योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से राज्यों को धक्का दिया जा रहा है।⁹ इसके अलावा, ति1:2021-22 के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित पूंजीगत व्यय लक्ष्य को पूरा करने पर, ग्यारह राज्यों को जीएसडीपी के 0.25 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त खुले बाजार उधार लेने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार, ति1 और ति2:2021-22 (चार्ट 11) के लिए राज्यों के पूंजीगत व्यय में सालाना आधार पर 98.5 प्रतिशत और 57.9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि देखी गई है।

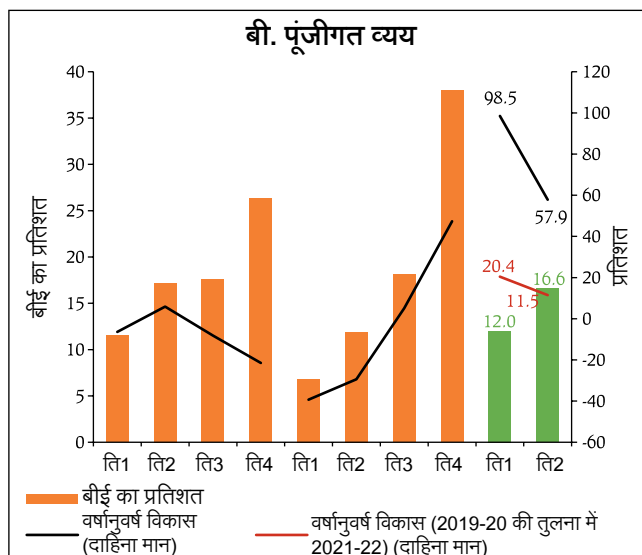
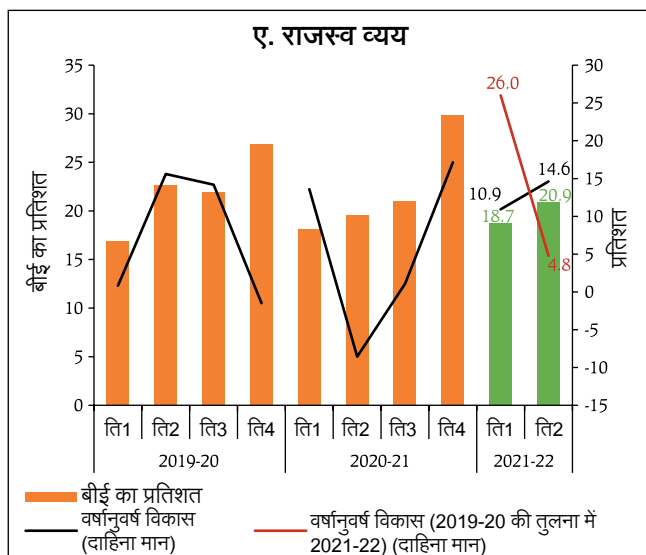
चार्ट 10: केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख सब्सिडी पर तिमाही व्यय



स्रोत: सीजीए और केंद्रीय बजट दस्तावेज़

⁹ इस योजना के तहत राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 2020-21 के लिए ₹12,000 करोड़ तक की राशि रखी गई थी और 2020-21 में राज्यों को ₹11,830.3 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। 29 अप्रैल, 2021 को, केंद्र ने पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त 50-वर्षीय ऋण के रूप में ₹15,000 करोड़ तक की अतिरिक्त राशि प्रदान करने के निर्णय की घोषणा की। 25 सितंबर, 2021 तक, केंद्र ने '2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता' नामक योजना के तहत 8 राज्यों में ₹2,903.8 करोड़ की पूंजीगत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने इन राज्यों, अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम और तेलंगाना को ₹1,393.8 करोड़ की राशि भी जारी की है।

चार्ट 11: राज्य सरकारों का तिमाही व्यय



स्रोत: सीजीए और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़

III. राजकोषीय घाटा और उसका वित्तपोषण

ए. राजकोषीय घाटा

केंद्र सरकार

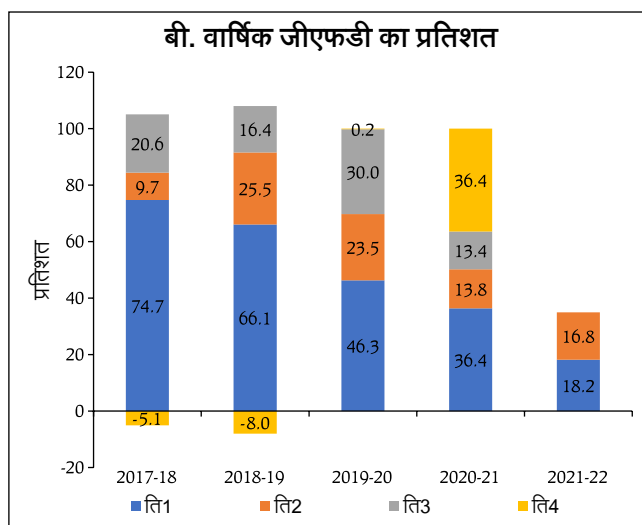
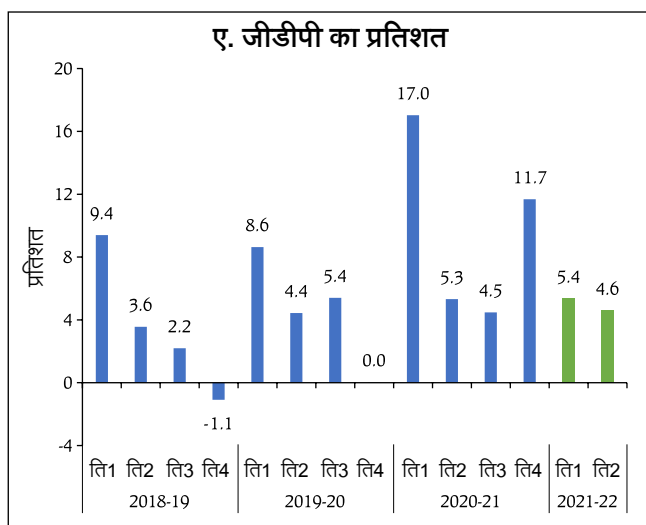
2020-21 (पीए) में सकल घरेलू उत्पाद का 9.2 प्रतिशत जीएफडी प्राप्त करने के बाद, संघ सरकार ने 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे की मध्यम अवधि के लक्ष्य के साथ 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.8 प्रतिशत के जीएफडी का बजट रखा

है। हालांकि, बेहतर राजस्व स्थिति और निहित व्यय के कारण, छमाही1: 2021-22 में केंद्र सरकार का जीएफडी, बजट अनुमान का 35.0 प्रतिशत है, जो पिछले वर्षों (चार्ट 12) की तुलना में बहुत कम है।

राज्य सरकारें

राज्यों ने 2021-22 के लिए जीडीपी के 3.7 प्रतिशत के जीएफडी का बजट रखा है, जबकि 2020-21 (आरई) में यह 4.7

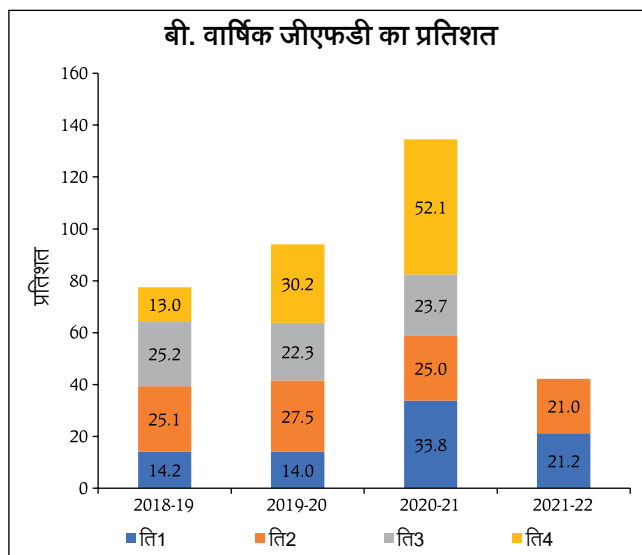
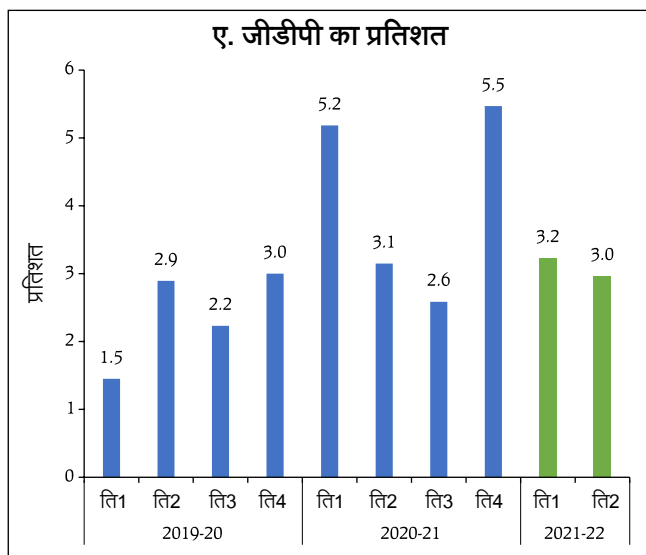
चार्ट 12: केंद्र का सकल राजकोषीय घाटा



नोट: चार्ट 12बी में 2017-18 से 2019-20 के लिए इस्तेमाल किया गया वार्षिक जीएफडी वास्तविक है; 2020-21 के लिए अनंतिम खाता है और 2021-22 के लिए बजट अनुमान के अनुसार है।

स्रोत: सीजीए और केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

चार्ट 13: राज्य का सकल राजकोषीय घाटा

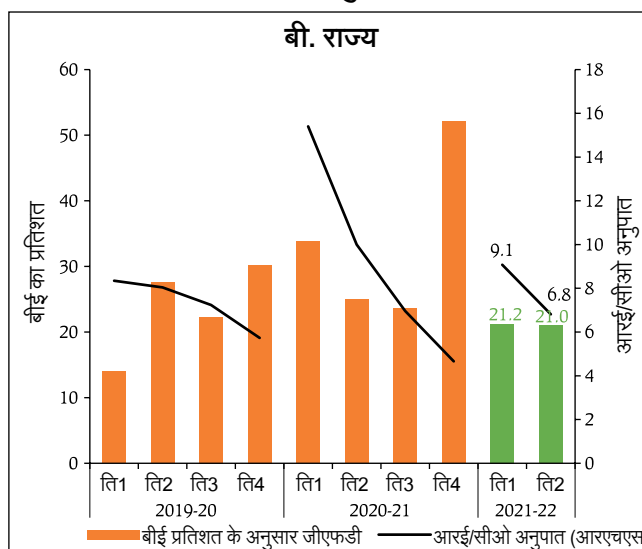
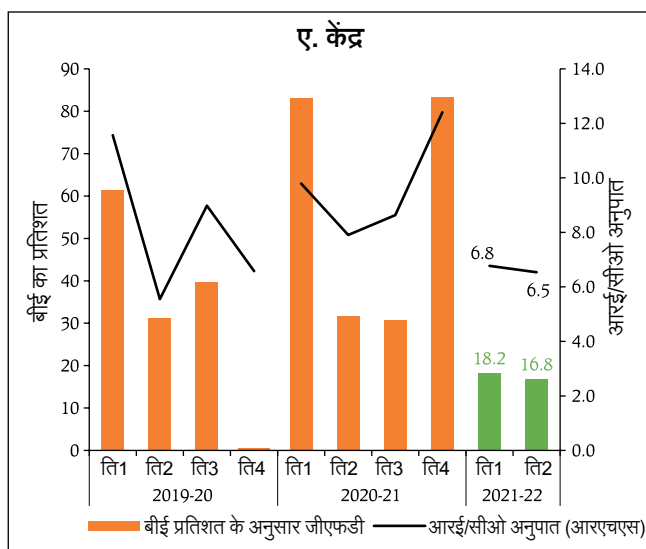


स्रोत: सीएजी; और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

प्रतिशत था। तिमाही-1: 2021-22 में, उनका जीएफडी, त्रैमासिक सकल घरेलू उत्पाद का 3.2 प्रतिशत है, जो कि तिमाही-1: 2020-21 की तुलना में कम है, लेकिन महामारी पूर्व के वर्षों में देखी गई प्रवृत्ति की तुलना में काफी अधिक है। छमाही-1: 2021-22 में, राज्यों का जीएफडी, बजट अनुमानों का 42.2 प्रतिशत है (चार्ट 13)।

केंद्र और राज्यों दोनों के लिए व्यय की गुणवत्ता, जो राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय (आरईसीओ) के अनुपात में मापा जाता है, छमाही-1: 2020-21 में -जब नई कैपेक्स परियोजनाएं शुरू करना महामारी के कारण गंभीर रूप से बाधित था - घटने के बाद अपने सामान्य स्तर पर वापस आ गया है। सरकारी व्यय की गुणवत्ता में सुधार अर्थव्यवस्था की मध्यम अवधि की विकास की संभावनाओं के लिए शुभ संकेत है (चार्ट 14)।

चार्ट 14: सकल राजकोषीय घाटा और केंद्र और राज्यों के लिए व्यय की गुणवत्ता



स्रोत: सीजीए; सीएजी; और केंद्रीय बजट दस्तावेज।

बी. जीएफडी का वित्तपोषण

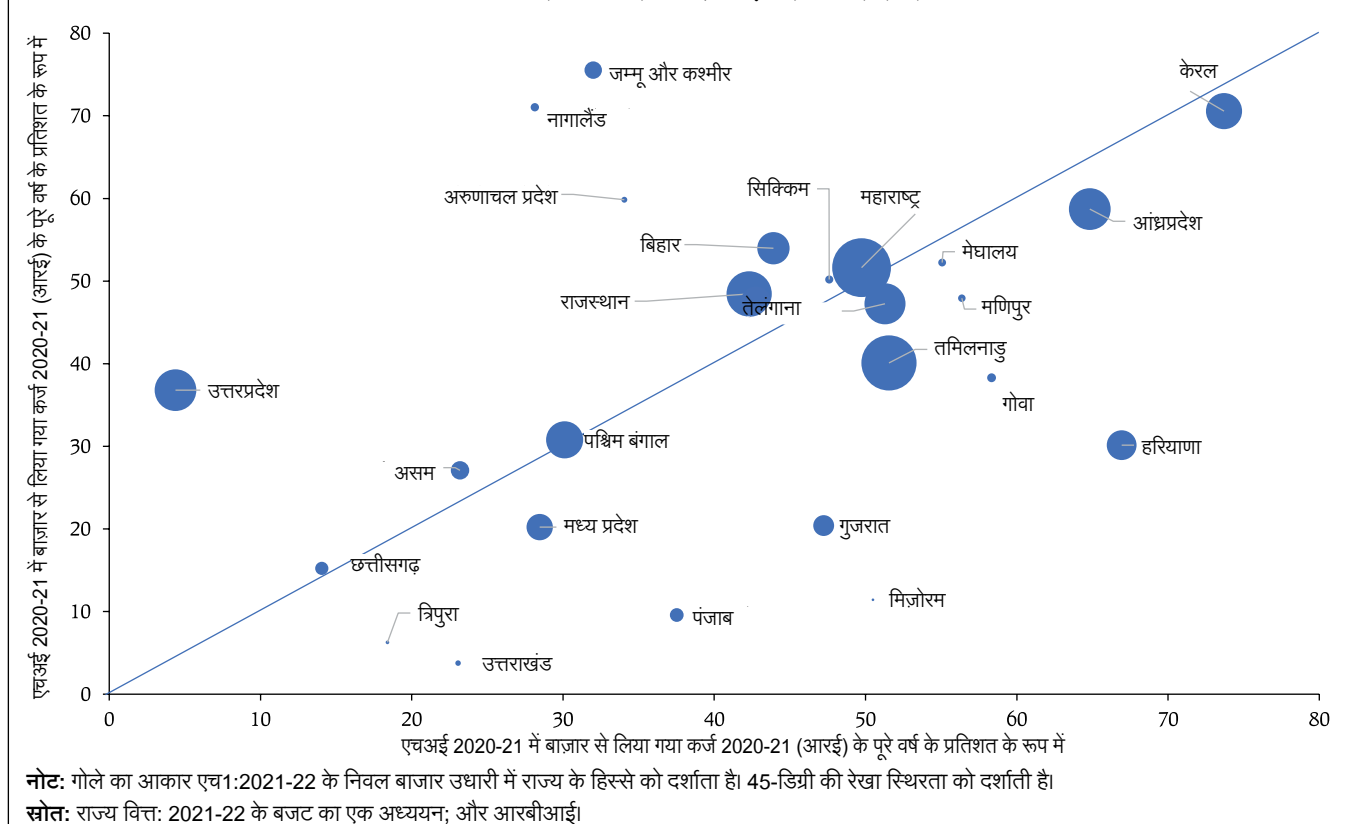
छमाही1: 2021-22 में, केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए बजटीय निवल बाजार उधार का 57.5 प्रतिशत पूरा किया, जिसने वर्ष की पहली छमाही के दौरान अपने जीएफडी के 90 प्रतिशत से अधिक का वित्त पोषण किया। छमाही1:2021-22 के दौरान केंद्र सरकार के उधार कार्यक्रम को सुचारू रूप से अंजाम दिया गया, जिसमें 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल 5.97 से 6.26 प्रतिशत के बीच था। यह भी उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक अतिरिक्त उधारी का सहारा लिए बिना अपने स्वयं के उधार कार्यक्रम के अंतर्गत जीएसटी संग्रह में कमी के लिए राज्यों को पूरी तरह से मुआवजा दिया।

राज्य-स्तरीय विश्लेषण से पहली छमाही के बाजार उधार (बजट अनुमान के प्रतिशत के अनुसार) में एक सामान्यीकृत गिरावट का पता चलता है। बड़े राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार और

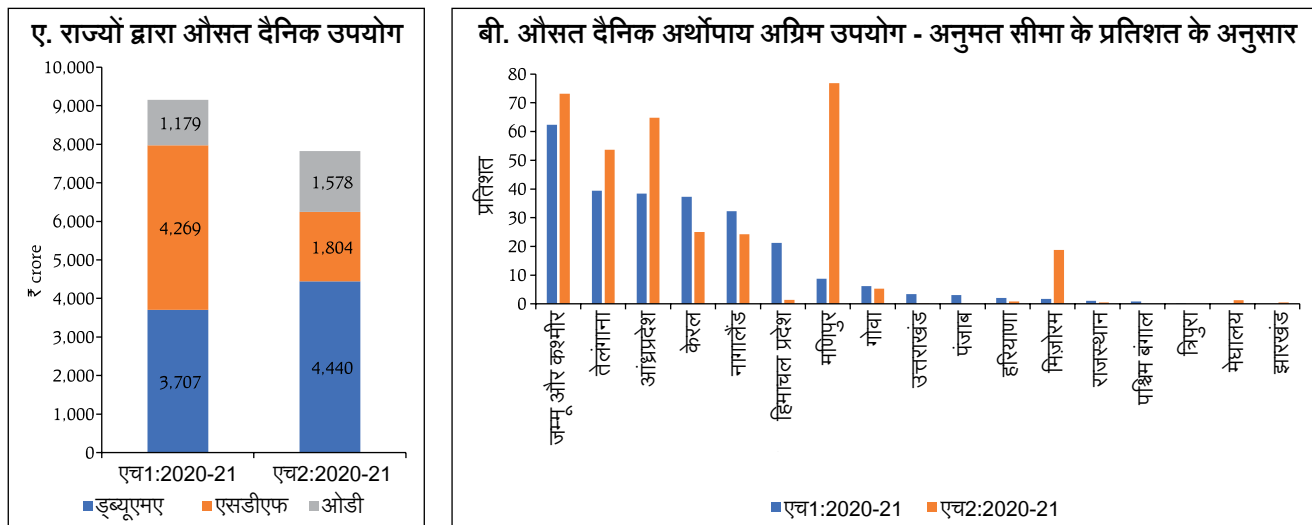
राजस्थान में छमाही1 उधार में वृद्धि देखी गई है। छमाही1:2021-22 में समग्र निवल बाजार उधार जो बजट अनुमान का 34.4 प्रतिशत था और छमाही1:2020-21 (चार्ट 15) की तुलना में वह 20 प्रतिशत कम था।

आरबीआई से विभिन्न सुविधाओं के तहत राज्यों द्वारा प्राप्त वित्तीय सुविधा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, छमाही1:2021-22 में कम हो गया¹⁰। तीनों सुविधाओं के तहत समग्र दैनिक उपयोग में छमाही1:2021-22 में वर्ष-दर-वर्ष 14.6 प्रतिशत की कमी देखी गई। समग्र रूप से, जहाँ, अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) और ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधाओं में छमाही1:2021-22 में दैनिक उपयोग में वृद्धि देखी गई है, वहीं विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के दैनिक उपयोग में 57.8 प्रतिशत की तीव्र गिरावट देखी गई है। प्रमुख राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम ने छमाही1:2021-22 में, छमाही1:2020-21

चार्ट 15: राज्य-वार निवल बाजार उधार-राशि



¹⁰ आरबीआई द्वारा राज्यों को विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (ओडी) के माध्यम से की वित्तीय सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

चार्ट 16: आरबीआई के पास उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के तहत राज्यों द्वारा उपयोग की गई वित्तीय सुविधा

नोट: चार्ट बी में केवल वे राज्य हैं जिन्होंने एच1:2020-21 या एच1:2021-22 में डब्ल्यूएमए सुविधा का लाभ उठाया है।

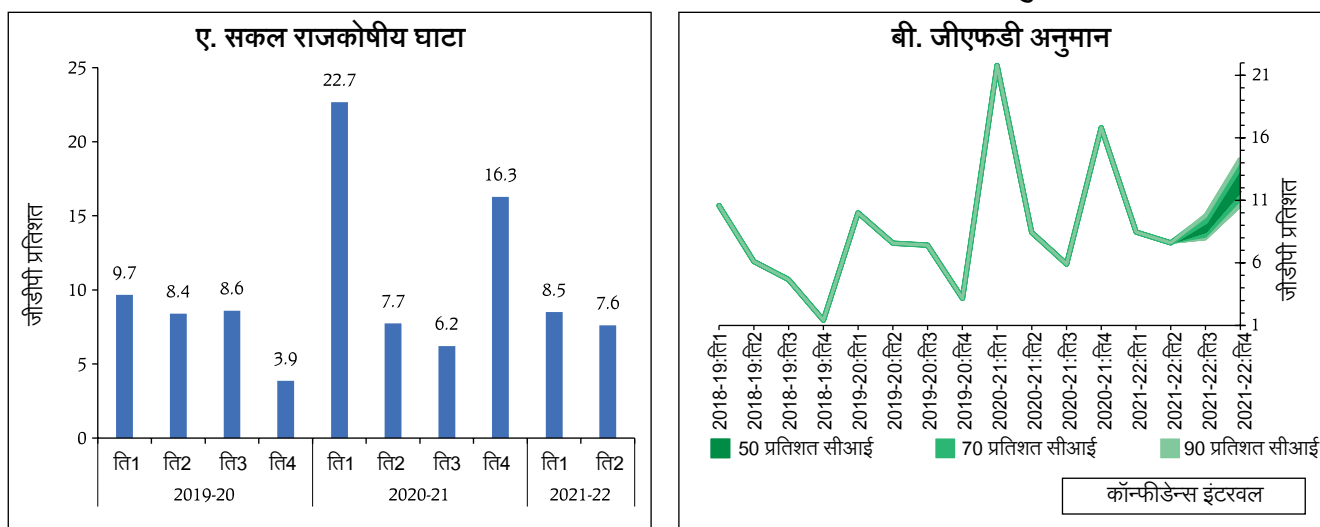
स्रोत: आरबीआई बुलेटिन कई अंक; और आरबीआई स्टाफ के आकलन।

(चार्ट 16) की तुलना में डब्ल्यूएमए के दैनिक उपयोग में वृद्धि देखी है।

IV. सामान्य सरकार वित्त

2021-22 (बीई) के लिए सामान्य सरकार जीएफडी को, 2020-21 (आरई) में 13.3 प्रतिशत से सकल घरेलू उत्पाद के

10.2 प्रतिशत तक समेकित करने का बजट किया गया। सामान्य सरकार पर, राजकोषीय आंकड़े समय पर उपलब्ध कराने के प्रयास को जारी रखते हुए, सामान्य सरकार की तिमाही वित्तीय स्थिति को 2021-22 की दूसरी तिमाही तक संकलित किया गया है। लीक से हटकर, 2020-21 की चौथी तिमाही में सामान्य

चार्ट 17: सामान्य सरकारी सकल राजकोषीय घाटा: वास्तविक और अनुमान

नोट: 1. मोटा हरा छायांकित क्षेत्र 50 प्रतिशत सीआई का प्रतिनिधित्व करता है जिसका अर्थ है कि 50 प्रतिशत संभावना है कि वास्तविक परिणाम घने हरे छायांकित क्षेत्र द्वारा दी गई सीमा के भीतर होगा। इसी तरह, 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत सीआई के लिए, क्रमशः 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत संभावना है, कि वास्तविक परिणाम संबंधित छायांकित क्षेत्रों द्वारा प्रतिनिधित्व की गई सीमा में होंगे।

2. वास्तविक संयुक्त जीएफडी-जीडीपी अनुपात केंद्र +27 राज्यों के लिए 2019-20 और 2020-21 के लिए है, और केंद्र +26 राज्यों के लिए ति1 और ति2: 2021-22 के लिए है।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का आकलन।

सरकार जीएफडी, 2020-21 की दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही की तुलना में अधिक निकला, जिसका मुख्य कारण मार्च 2021 में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के पिछले बकाया को बजट प्रावधान में शामिल करना है। केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा राजस्व जुटाने में सुधार के कारण, सामान्य सरकारी जीएफडी तिमाही-1 और तिमाही-2: 2021-22 में मंद रहा। आगे बढ़ते हुए, जबकि कर संग्रह में तिमाही-3 और तिमाही-4 में उछाल रहने की उम्मीद है, अपेक्षित व्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप, सामान्य सरकार घाटा, तिमाही-3 और तिमाही-4 (अनुमानित) में सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 8.9 प्रतिशत और 12.9 प्रतिशत हो सकता है। तदनुसार, जीएफडी, छमाही1:2021-22 में जीडीपी के 8.0 प्रतिशत से बढ़कर छमाही 2: 2021-22 में 10.9 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

V. निष्कर्ष

2020-21 में महामारी के कारण सामान्य सरकार राजकोषीय घाटे के व्यापक विस्तार के बाद, केंद्र और राज्यों दोनों ने वृद्धि के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता को बनाए रखते हुए भी अपने 2021-22 के बजट में भरोसेमंद राजकोषीय दृढ़ता के प्रति

प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। छमाही1:2021-22 के दौरान, अनुमानित राजकोषीय दृढ़ता का अनुसरण करते हुए एक उत्साहजनक सुधार दिखा, जिसमें, तिमाही-2 :21-22 में जीडीपी महामारी-पूर्व के स्तर तक बढ़ा गया। कर राजस्व में तेज वृद्धि, बेहतर कर प्रशासन और पूंजीगत व्यय में वृद्धि, मध्यम अवधि में सतत वृद्धि पुनरुत्थान और राजकोषीय समेकन दोनों को प्राप्त करने हेतु अच्छे संकेत हैं। पूंजी परिव्यय के भीतर, हालांकि, केंद्र और राज्यों दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे उन क्षेत्रों के लिए व्यय को चैनलाइज़ करें जो निजी निवेश में परिणत हों और अंतर-सामयिक और अंतर-क्षेत्रीय संबंधों के आधार पर गुणक प्रभावों को इष्टतम बना सकें जो उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता को बढ़ावा दे। आगे बढ़ते हुए, वायरस के नए ओमाइक्रोन संस्करण से जुड़ी नई चिंताओं के बावजूद, जैसा कि आर्थिक पुनरुत्थान ने और अधिक गति प्राप्त की है, केंद्र और राज्यों को राजकोषीय नीति सामान्यीकरण की दिशा में विश्वसनीय मध्यम अवधि के दिशानिर्देश प्रदान करने चाहिए ताकि भविष्य के आर्थिक झटके, यदि कोई हों, से निपटने के लिए राजकोषीय बफर को फिर से भरा जा सके।

परिशिष्ट सारणी

सारणी 1: अप्रैल-सितंबर 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार की बजटीय स्थिति								
मद	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)			
	वास्तविक		बजट अनुमान		बजट अनुमान का प्रतिशत		वर्ष दर वर्ष विकास दर	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. राजस्व प्राप्तियां	1081.0	550.8	1788.4	2020.9	60.4	27.3	96.3	-32.5
1.1. निवल कर राजस्व	920.7	458.5	1545.4	1635.9	59.6	28.0	100.8	-24.5
1.2. गैर-कर राजस्व	160.4	92.3	243.0	385.0	66.0	24.0	73.8	-55.9
1.3. ब्याज प्राप्तियां	10.3	5.7	11.5	11.0	89.3	52.1	79.4	-11.3
2. पूंजीगत प्राप्तियाँ	18.1	14.6	188.0	225.0	9.6	6.5	23.8	-28.9
2.1. ऋण की वसूली	9.0	8.9	13.0	15.0	69.3	59.2	1.7	7.5
2.2. अन्य प्राप्तियां	9.1	5.8	175.0	210.0	5.2	2.8	57.7	-53.2
3. कुल प्राप्तियाँ (1+2)	1099.2	565.4	1976.4	2245.9	55.6	25.2	94.4	-32.5
4. राजस्व व्यय	1396.7	1313.6	2929.0	2630.1	47.7	49.9	6.3	1.0
जिसमें से								
(i) ब्याज भुगतान	363.8	305.7	809.7	708.2	44.9	43.2	19.0	12.9
5. पूंजीगत व्यय	229.4	165.8	554.2	412.1	41.4	40.2	38.3	-11.6
जिसमें से								
(i) ऋण और अग्रिम	19.5	17.4	40.4	31.8	48.3	54.7	12.3	17.1
6. कुल व्यय (4+5)	1626.0	1479.4	3483.2	3042.2	46.7	48.6	9.9	-0.6
7. राजस्व घाटा (4-1)	315.6	762.8	1140.6	609.2	27.7	125.2	-58.6	57.4
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	526.9	914.0	1506.8	796.3	35.0	114.8	-42.4	40.3
9. सकल प्राथमिक घाटा {8-4 (i)}	163.1	608.3	697.1	88.1	23.4	690.2	-73.2	59.7

स्रोत: लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी 2: केंद्र सरकार के वित्त की त्रैमासिक स्थिति										
मद	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)					
	ति1		ति2		बजट अनुमान का प्रतिशत				वर्ष दर वर्ष विकास दर	
					ति1		ति2		2021-22	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	ति1	ति2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. राजस्व प्राप्तियाँ	540.0	150.0	541.1	400.8	30.2	7.4	30.3	19.8	260.0	35.0
1.1. निवल कर राजस्व	412.7	134.8	508.0	323.7	26.7	8.2	32.9	19.8	206.1	56.9
1.2. गैर कर राजस्व	127.3	15.2	33.0	77.1	52.4	3.9	13.6	20.0	738.4	-57.1
1.3. ब्याज प्राप्तियाँ	4.7	1.6	5.6	4.1	40.5	14.8	48.9	37.3	186.6	36.9
2. पूँजीगत प्राप्तियाँ	7.4	3.6	10.7	11.1	3.9	1.6	5.7	4.9	107.2	-3.1
2.1. ऋण की वसूली	3.4	3.6	5.6	5.3	26.2	23.9	43.1	35.3	-4.7	6.0
2.2. अन्य प्राप्तियाँ	4.0	0.0	5.1	5.8	2.3	0.0	2.9	2.8		-11.5
3. कुल प्राप्तियाँ (1+2)	547.4	153.6	551.8	411.8	27.7	6.8	27.9	18.3	256.4	34.0
4. राजस्व व्यय	710.1	727.7	686.5	585.9	24.2	27.7	23.4	22.3	-2.4	17.2
जिसमें से										
(i) ब्याज भुगतान	184.3	160.5	179.5	145.2	22.8	22.7	22.2	20.5	14.8	23.6
5. पूँजीगत व्यय	111.5	88.3	117.9	77.6	20.1	21.4	21.3	18.8	26.3	51.9
जिसमें से										
(i) ऋण और अग्रिम	6.6	13.9	12.9	3.4	16.4	43.9	31.9	10.8	-52.5	276.6
6. कुल व्यय (4+5)	821.6	815.9	804.4	663.5	23.6	26.8	23.1	21.8	0.7	21.2
7. राजस्व घाटा (4-1)	170.2	577.7	145.5	185.1	14.9	94.8	12.8	30.4	-70.5	-21.4
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	274.2	662.4	252.6	251.6	18.2	83.2	16.8	31.6	-58.6	0.4
9. सकल प्राथमिक घाटा (8-4 (i))	90.0	501.9	73.1	106.5	12.9	569.4	10.5	120.8	-82.1	-31.3

स्रोत: लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी 3: अप्रैल-सितंबर 2021 के दौरान राज्य सरकारों की बजटीय स्थिति								
मद	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)			
	वास्तविक		बजट अनुमान		बजट अनुमान का प्रतिशत		वर्ष दर वर्ष विकास दर	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. राजस्व प्राप्तियाँ	1,174.3	926.7	3,190.5	3,070.6	36.8	30.2	26.7	-14.6
1.1. कर राजस्व	853.5	652.0	2,172.5	2,181.7	39.3	29.9	30.9	-19.5
1.2. गैर कर राजस्व	83.3	56.7	254.4	250.5	32.7	22.6	46.9	-19.4
1.3. सहायता अनुदान और योगदान	237.6	218.0	763.6	638.4	31.1	34.2	9.0	6.0
2. पूँजीगत प्राप्तियाँ	4.7	2.3	21.0	18.1	22.2	12.7	102.2	-81.5
2.1. ऋण और अग्रिमों की वसूली	4.6	2.2	14.4	14.2	31.5	15.8	102.6	-81.8
2.2. अन्य प्राप्तियाँ	0.1	0.1	6.6	3.9	1.5	1.4	87.1	-11.3
3. कुल प्राप्तियाँ	1,179.0	929.0	3,211.5	3,088.7	36.7	30.1	26.9	-15.4
4. राजस्व व्यय	1,322.2	1,171.8	3,342.1	3,111.5	39.6	37.7	12.8	0.9
4.1. व्याज भुगतान	154.7	145.3	417.8	370.5	37.0	39.2	6.4	11.5
5. पूँजीगत व्यय	185.7	107.5	648.5	573.5	28.6	18.8	72.7	-33.4
5.1. पूँजी परिव्यय	171.2	97.4	595.2	530.0	28.8	18.4	75.8	-31.5
6. कुल व्यय	1,508.0	1,279.4	3,990.5	3,685.0	37.8	34.7	17.9	-3.3
7. राजस्व घाटा (4-1)	147.9	245.2	151.5	40.9	97.6	599.5	-39.7	223.2
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	329.0	350.4	779.0	596.4	42.2	58.8	-6.1	55.9
9. सकल प्राथमिक घाटा {8-4 (i)}	174.33	205.07	361.23	225.88	48.3	90.8	-15.0	117.2

नोट: डेटा 26 राज्यों से संबंधित है।

स्रोत: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।

सारणी 4: राज्य सरकार के वित्त की त्रैमासिक स्थिति										
मद	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)					
	वास्तविक				बजट अनुमान का प्रतिशत				वर्ष दर वर्ष विकास दर	
	ति1		ति2		ति1		ति2		2021-22	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	ति1	ति2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. राजस्व प्राप्ति	535.5	400.6	638.8	526.1	16.8	13.0	20.0	17.1	33.7	21.4
1.1. कर राजस्व	378.4	262.4	475.1	389.6	17.4	12.0	21.9	17.9	44.2	21.9
1.2. गैर कर राजस्व	37.8	27.0	45.4	29.7	14.9	10.8	17.9	11.8	40.2	53.1
1.3. सहायता अनुदान और योगदान	119.3	111.2	118.3	106.9	15.6	17.4	15.5	16.7	7.3	10.7
2. पूँजीगत प्राप्ति	2.1	0.8	2.5	1.5	10.1	4.2	12.0	8.6	182.4	63.3
2.1. ऋण और अग्रिमों की वसूली	2.1	0.7	2.4	1.5	14.6	5.2	16.9	10.6	186.9	61.6
2.2. अन्य प्राप्ति	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.5	1.3	0.9	-6.6	133.3
3. कुल प्राप्ति	537.7	401.3	641.3	527.6	16.7	13.0	20.0	17.1	34.0	21.5
4. राजस्व व्यय	625.2	563.6	697.0	608.2	18.7	18.1	20.9	19.5	10.9	14.6
4.1. ब्याज भुगतान	66.5	65.0	88.2	80.3	15.9	17.6	21.1	21.7	2.2	9.8
5. पूँजीगत व्यय	78.0	39.3	107.7	68.3	12.0	6.9	16.6	11.9	98.5	57.9
5.1. पूँजी परिव्यय	68.9	36.6	102.3	60.8	11.6	6.9	17.2	11.5	88.3	68.3
6. कुल व्यय	703.2	602.9	804.8	676.5	17.6	16.4	20.2	18.4	16.6	19.0
7. राजस्व घाटा	89.7	163.0	58.3	82.1	59.2	398.7	38.5	200.8	-45.0	-29.0
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	165.5	201.6	163.5	148.8	21.2	33.8	21.0	25.0	-17.9	9.8
9. सकल प्राथमिक घाटा (8 - 4.1)	99.1	136.6	75.3	68.5	27.4	60.5	20.8	30.3	-27.5	9.9

नोट: डेटा 26 राज्यों से संबंधित है।

स्रोत: भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक।

सारणी 5: कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का कालक्रम (मार्च 2021 के बाद)	
घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
30 मार्च, 2021	केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 30,000 करोड़ रुपये के साथ-साथ राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों को आईजीएसटी तदर्थ निपटान के रूप में 28,000 करोड़ रुपये जारी किए।
31 मार्च, 2021	- आधार नंबर की सूचना देने और उसे स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी गई थी। - परिवाद निपटान पैनल (डीआरपी) द्वारा जारी निर्देश के लिए परिणामी आदेश पारित करने और समानीकरण लेवी विवरणों को प्रोसेस करने के लिए समय-सीमा को 30 अप्रैल, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। - ईसीएलजीएस 1.0 और 2.0 की वैधता को 30 जून, 2021 तक या 3 लाख करोड़ रुपये की राशि के लिए गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया गया था। - ECLGS 3.0 को आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन, अवकाश और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए पेश किया गया था जो निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं। योजना के तहत वितरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दिया गया है। - एमओएफ ने वित्त वर्ष 2020-21 में राज्यों को 2020-21 के संशोधित अनुमानों के अलावा अतिरिक्त न्यागमन के रूप में 45,000 करोड़ रुपये जारी किए।
1 अप्रैल, 2021	- केन्द्र ने आर्थिक सुधार को समय पर बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत राज्यों को 11,830 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। - केंद्र ने वित्त वर्ष 2020-21 में राज्यों को अतिरिक्त न्यागमन के रूप में 45,000 करोड़ रुपये जारी किए, जो 2020-21 (आरई) की तुलना में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि है।
22 अप्रैल, 2021	कतिपय नकदी प्रबंधन दिशानिर्देशों से केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय के लिए एक अस्थायी छूट प्रदान की गई है जो बड़े भुगतानों को जारी करने के समय को निर्धारित करती है ताकि महीने /तिमाही के दौरान कर राजस्व के अंतर्वाह के साथ उनका मिलान किया जा सके।
23 अप्रैल, 2021	मई और जून 2021 के दौरान प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत मुफ्त अनाज के वितरण की घोषणा की गई थी।
24 अप्रैल, 2021	- प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत भुगतान की समय सीमा, एक अतिरिक्त राशि के बिना, 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी गई। - आयकर अधिनियम के तहत आदेश पारित करने के लिए विभिन्न समय सीमाओं को 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। - मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन थेरेपी से संबंधित उपकरण जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंक आदि और कोविड-19 टीकों को 31 जुलाई, 2021 तक मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई है।
30 अप्रैल, 2021	- बिना सीमा शुल्क मंजूरी के पोस्ट या कूरियर के माध्यम से ई-कॉमर्स पोर्टलों से खरीदे गए व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात में 31 जुलाई, 2021 तक छूट। - आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर देय जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है। - COVID-19 टेस्टिंग प्रयासों को पूरा करने हेतु, इंप्लेमेंटरी डायमोनोस्टिक (मार्कर) किट और रेमडेसिविर इंजेक्शन के आयात पर 31 अक्टूबर तक मूल सीमा शुल्क से छूट। - भारत सरकार ने पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए ब्याज मुक्त 50 साल के ऋण के रूप में राज्यों को 15,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त राशि प्रदान करने की घोषणा की। इस समग्र सीमा का एक तिहाई उन राज्यों को प्रदान किया जाएगा जो मुद्राकरण और / या अपनी परिसंपत्तियों का, उनके द्वारा प्राप्त राशि के 33 से 100 प्रतिशत की सीमा में विनिवेश करते हैं।

(जारी...)

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
1 मई, 2021	- एक विशेष व्यवस्था के रूप में, केंद्र सरकार ने सामान्य समय से पहले, सभी राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के लिए केंद्रीय हिस्से की 2021-22 की पहली किस्त ₹8,874 करोड़ जारी की है। इस राशि का 50 प्रतिशत तक राज्यों द्वारा कोविड-19 रोकथाम उपायों के लिए उपयोग किया जा सकता है। - आयकर अधिनियम के तहत विभिन्न अनुपालनों के लिए समय सीमा 31 मई, 2021 तक बढ़ा दी गई है।
2 मई, 2021	जीएसटी भुगतानकर्ताओं के लिए राहत के उपाय - विलंबित कर भुगतान के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सामान्य ब्याज दर के बदले ब्याज की रियायती दें। - कर अवधि मार्च 2021 और अप्रैल 2021 के लिए नियत तिथि से परे प्रस्तुत फॉर्म GSTR-3B में रिटर्न के संबंध में 15 दिनों के लिए विलंब शुल्क माफ कर दिया गया। - जीएसटी अधिनियम के तहत किसी भी प्राधिकरण या किसी भी व्यक्ति द्वारा विभिन्न कार्यों को पूरा करने की समय सीमा, जो 15 अप्रैल, 2021 से 30 मई, 2021 तक की अवधि के दौरान आती है, को 31 मई, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
3 मई, 2021	कोविड-19 राहत सामग्री (पहले से ही सीमा शुल्क से छूट) के आयात पर आईजीएसटी से छूट जो 30 जून, 2021 तक मुफ्त वितरण के लिए भारत के बाहर से दान/प्राप्त किया गया।
9 मई, 2021	केंद्र ने ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को अनुदान प्रदान करने के लिए 25 राज्यों को ₹8,923.8 करोड़ की राशि जारी की। जारी की गई राशि वर्ष 2021-22 के लिए 'अनटाइड ग्रांट' की पहली किस्त थी, जिसका उपयोग आरएलबी द्वारा अन्य बातों के अलावा, COVID-19 महामारी से निपटने के लिए आवश्यक विभिन्न रोकथाम और शमन उपायों के लिए किया जाएगा।
19 मई, 2021	14,775 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी की घोषणा की गई थी।
20 मई, 2021	आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कतिपय अनुपालनों के लिए समय-सीमा बढ़ा दी गई थी।
28 मई, 2021	43वीं जीएसटी परिषद की बैठक ने आईजीएसटी से 31 अगस्त, 2021 तक कई निर्दिष्ट COVID-19 संबंधित सामानों जैसे कि चिकित्सा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य ऑक्सीजन भंडारण और परिवहन उपकरण, कुछ डायग्नोस्टिक मार्कर परीक्षण किट और COVID-19 टीके, आदि के लिए पूर्ण छूट की सिफारिश की। - परिषद ने COVID-19 संबंधित राहत उपाय के रूप में GST करदाताओं को कुछ छूट देने की भी सिफारिश की।
30 मई, 2021	आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को ऑनसाइट ऑक्सीजन उत्पादन, ईसीएलजीएस 3.0 के व्यापक कवरेज और ईसीएलजीएस 1.0 के लिए अवधि में वृद्धि के लिए ईसीएलजीएस 4.0 के साथ विस्तारित किया गया था।
12 जून, 2021	44वीं जीएसटी परिषद ने 30 सितंबर, 2021 तक COVID-19 राहत और प्रबंधन में उपयोग की जा रही विशिष्ट वस्तुओं पर GST दरों को कम कर दिया।
25 जून, 2021	सरकार ने आयकर अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अनुपालन की समय-सीमा में और विस्तार दिया और COVID-19 उपचार पर खर्च के लिए कर छूट और COVID-19 के कारण मृत्यु पर प्राप्त अनुग्रह राशि की घोषणा की।
28 जून, 2021	- स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना की घोषणा की गई थी। - ईसीएलजीएस का विस्तार स्वीकार्य गारंटी की समग्र सीमा के साथ किया गया था, जिसे 3 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था। - सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना की घोषणा की गई।

(जारी...)

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
	5 लाख पर्यटकों को एक महीने का मुफ्त पर्यटक वीजा या 31 मार्च, 2022 तक, जो भी पहले हो। - आत्मा निर्भर भारत रोजगार योजना (ANBRY) के तहत पंजीकरण की तारीख 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई थी। - पीएमजीकेवाई के तहत मुफ्त अनाज के प्रावधान को नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। 23,220 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और मानव संसाधनों को मजबूत करने के लिए एक योजना की घोषणा की गई थी, जिसमें अल्पकालिक आपातकालीन तैयारियों और बच्चों और बाल चिकित्सा देखभाल / बाल चिकित्सा बिस्तरों पर विशेष जोर दिया गया था। - जलवायु प्रतिरोध विशेष फसल किस्मों की रिलीज की घोषणा की गई थी। - पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एनईआरएएमएसी) के लिए 7745 करोड़ रुपये का पुनरुद्धार पैकेज प्रदान किया जाएगा। - परियोजना निर्यात के लिए 33,000 करोड़ रुपये का बढ़ावा राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते (एनईआईए) के माध्यम से प्रदान किया गया था। - निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) में 5 वर्षों में इक्विटी निवेश की घोषणा निर्यात बीमा कवर को 88,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए की गई थी। - भारत नेट पीपीपी मॉडल के माध्यम से प्रत्येक गांव को ब्रॉडबैंड के लिए 19,041 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे। - बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। - सुधार-आधारित परिणाम-लिंकड विद्युत वितरण योजना के लिए ₹3.03 लाख करोड़ की घोषणा की गई थी, जिसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा ₹97,631 करोड़ होगा। - पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन और मुख्य अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए नई सुव्यवस्थित प्रक्रिया तैयार की जाएगी।
14 जुलाई, 2021	केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, परिधान / वस्त्र और मेड-अप के निर्यात पर, निर्यात उत्पादों पर कर और ड्यूटी की छूट (आरओडीटीईपी) योजना से अलग, राज्य और केंद्रीय करों और उगाही (आरओएससीटीएल) की छूट को उसी दरों के साथ, जैसा कि मार्च 2019 में कपड़ा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था, जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। यह योजना 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी।
27 जुलाई, 2021	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 13.07.2021 को राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को "कोविड-19 के बफर स्टॉक प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश" जारी किए, जिसमें उनसे भविष्य में मामलों में किसी भी संभव उछाल के लिए दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से आवश्यक खरीद प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने का अनुरोध किया गया था।
29 अगस्त, 2021	विलंब शुल्क माफी योजना की अंतिम तिथि और जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण रद्द करने के निरस्तीकरण के लिए आवेदन दायर करने की समय सीमा बढ़ा दी गई थी।
14 सितंबर, 2021	वित्तीय मंत्रालय द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित लक्ष्य को ग्यारह राज्यों ने 2021-22 की पहली तिमाही में हासिल किया। प्रोत्साहन के रूप में, इन राज्यों को व्यय विभाग द्वारा ₹15,721 करोड़ की अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति दी गई थी। दिया गया अतिरिक्त खुला बाजार उधार अनुमति उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.25 प्रतिशत के बराबर है।
17 सितंबर, 2021	सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा, आयकर अधिनियम के तहत दंड की कार्यवाही पूरी करने की नियत तिथि और बेनामी संपत्ति लेनदेन प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के तहत निर्णायक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय सीमा बढ़ा दी है।

(जारी...)

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
	45वीं GST परिषद ने कुछ COVID-19 उपचार दवाओं पर मौजूदा रियायती GST दरों को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाने और कुछ और COVID-19 उपचार दवाओं पर GST दर को 31 दिसंबर, 2021 तक घटाकर 5 प्रतिशत करने की सिफारिश की। - केंद्र ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए 11 राज्यों को 2,427 करोड़ रुपये की राशि जारी की। जारी की गई राशि वर्ष 2021-22 के लिए बंधे हुए अनुदान की पहली किस्त है।
25 सितंबर, 2021	केंद्र ने '2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता' नामक योजना के तहत 8 राज्यों में 2,903.80 करोड़ रुपये की पूंजीगत परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन राज्यों को 1,39383 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
29 सितंबर, 2021	ईसीएलजीएस की समयसीमा को 31.03.2022 तक या योजना के तहत 4.5 लाख करोड़ रुपये की राशि की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा, इस योजना के तहत संवितरण की अंतिम तिथि को 30.06.2022 तक बढ़ा दिया गया था और कोविड की दूसरी लहर से प्रभावित व्यवसायों को समर्थन देने के लिए योजना में कुछ संशोधन किए गए थे।
1 अक्टूबर, 2021	केंद्र ने 25.09.2021 को एक आदेश जारी किया, जिसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत सहायता की वस्तुओं और मानदंडों को संशोधित किया गया, जिसमें कोविड -19 के कारण मृतक के परिजनों को अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया। राज्य सरकारों के पास वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, एसडीआरएफ में उपलब्ध प्रारंभिक शेष राशि के अलावा, राज्य का हिस्सा सहित उनके एसडीआरएफ में ₹ 23,186.40 करोड़ की राशि होगी, जो उन्हें, COVID-19 के कारण मृतक के परिजन और अन्य अधिसूचित आपदाओं पर राहत प्रदान करने हेतु अनुग्रह राशि प्रदान करने के खर्च को पूरा करने के लिए होगा।
24 नवंबर, 2021	पीएमजीकेवाई, जिसके तहत लाभार्थियों को उनके सामान्य मासिक कोटे के अलावा 5 किलोग्राम गेहूं या चावल प्रदान किया जाता है, को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था।